

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि मामलों,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानियन्त्रक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
देवीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

दिनांक : 21 नवम्बर, 2006

विषय: मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, देवीताल में स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री पन्त जी के आवास(सी०आई०डी०ब्लॉक) में रंगई-पुताई एवं मरम्मत के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2566/UHC/Admin.B/Const./2006, दिनांक 29.9.2006 के संदर्भ में भुझे यह बताने का सिलसिला हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, देवीताल में स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री पन्त जी के आवास(सी०आई०डी०ब्लॉक) में रंगई-पुताई एवं मरम्मत के कार्य हेतु ₹0 1,55,000/- के आगमन के विस्तृत टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत ₹0 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत के आगमन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹0 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय विवरण ज्ञान की भी स्वीकृति महामहिम सम्मानित निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगमन में उल्लिखित दरों का विवरण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों का, जो दरें सिडयून ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव में ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व सम्स्त कार्यों के विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त की जाए, तदनुसार ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा को स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एक भूखण्ड प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (5) विपरीत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्स्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित दरे/विनिर्दिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के परन्तु आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) आगमन में धनराशि तिन मरों हेतु स्वीकृत की गई है, अभी धर में कार्य जारी है । एक मर को सलित दूसरी मर में किसी भी तरह में खर्च न की जाय ।
- (8) कार्य करते समय यह सुनिश्चित करने कि वार्षिक अनुसंधान से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस में अधिक किसी भी स्थिति में खर्च न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

- (10) व्यय से पूर्व चञ्चल मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर धरोहर कलम, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर विरत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं मितव्ययता हेतु सम्बन्धित निर्माण गृहन्मा/अधीनस्थ अधीनता पूर्णरूप में उत्तरदायी होंगे ।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग का स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय व्ययक को अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत संज्ञा-गोपक "2014 न्याय प्रशासन-00-अधीनस्थ-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुक्षण" के नामे हाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश विल अनुभाग-5 के अग्रासकीय संख्या-665/XXVI(5)/2006, दिनांक 9.11.06 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भारतीय,

(आर.डी.एस.काल)

मन्त्रि ।

संख्या 34 पो[2]/XXXVI(1)/2006-तद्विषयक ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों), आचार्य बिल्डिंग, उत्तरांचल, मानस, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अधीनस्थ, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधीनस्थ अधीनस्थ, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/विल अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन.डी.ओ./सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अनिल कुमार वर्मा)

आर सचिव ।

(4)